बगैर लड़े शत्रु को अपने वश में करना ही युद्ध की सर्वोच्च कला है। - सन त्जू

लैंसेट के अध्ययन के अनुसार, करीब 50 फीसदी भारतीय शारीरिक श्रम से दूर भागने वाले हैं और अगर स्थितियां न सुधरीं, तो 2030 तक यह आंकड़ा साठ फीसदी तक पहुंचने की आशंका है। ऐसे में, समय रहते चेतना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ व सक्रिय भारत ही सही मायनों में विकसित भारत की ओर बढ़ सकता है।

ये सुस्ती क्यों

दो लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन का यह कहना कि करीब पचास फीसदी भारतीय विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सेहत के न्यूनतम मापदंडों पर खरे नहीं उतरते, स्वास्थ्य के प्रति हमारी लापरवाही को तो दर्शाता ही है, इस चिंताजनक तथ्य को भी रेखांकित करता है कि बड़ी संख्या में लोग अपनी जीवन-शैली में सुधार करने की जरूरत को नजर अंदाज कर रहे हैं। यह चिंताजनक इसलिए भी है कि आंकड़े और भी बदतर होती स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। वर्ष 2000 में देश में 22 फीसदी वयस्क शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं थे, तो 2010 में यह आंकड़ा 34 फीसदी और अब तो यह करीब 50 फीसदी तक पहुंच गया है। महिलाओं (57 फीसदी) की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है, जो पुरुषों (42 फीसदी) की तुलना में ज्यादा निष्क्रिय हैं। इसकी वजह दरअसल यह है कि ज्यादातर महिलाएं घरेलू काम को शारीरिक व्यायाम का विकल्प मानती हैं, जो आंशिक तौर पर ही सच है। फिर उनके समक्ष सांस्कृतिक बाधाएं भी होती हैं। ज्यादातर घरेलू महिलाएं घर की देखभाल के कामों में इस कदर डूब जाती हैं कि वे अपनी ही प्राथमिकता में खुद को पीछे धकेल देती हैं। रिपोर्ट का यह कहना भी चिंताजनक है कि भारतीय महिलाएं पड़ोसी देशों बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से भी बदतर स्थिति में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अगर कोई वयस्क प्रति सप्ताह 150 मिनट की मध्यम तीव्रता की या 75 मिनट की ज्यादा तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि नहीं करता, तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा। बावजूद इसके कि भारतीयों में आनुवंशिक रूप से दूसरों की तुलना में हृदय रोग व मधुमेह जैसी गैर-संचारी बीमारियों के काम से कम एक दशक पहले विकसित होने का खतरा ज्यादा होता है, अगर देश के वयस्क शारीरिक गतिविधियों में भी कमी ला रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वे अपने लिए ही जोखिम बढ़ा रहे हैं। दरअसल, भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में बढ़ते शहरीकरण ने उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है, जिससे एक

आरामदायक जीवन-शैली पैदा हुई है। यही वजह है, जैसा रिपोर्ट से भी पता चलता है, कि दुनिया के 195 देशों में से भारत अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि के मामले में 12वें स्थान पर पहुंच गया है और अगर चीजें नहीं सुधरीं, तो 2030 तक पर्याप्त शारीरिक श्रम न करने की वजह से देश की साठ फीसदी आबादी पर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा होगा। ऐसे में, यह बेहद जरूरी है कि लैंसेट के निष्कर्षों में निहित संदेश को पूरी गंभीरता से समझते हुए अपनी जीवन-शैली में सुधार किया जाए, क्योंकि स्वस्थ व सक्रिय भारत ही सच्चे अर्थों में प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन की दिशा में बढ़ सकता है।

बीजिंग की बौखलाहट

विशेषज्ञों का कहना है कि तिब्बत के बारे में भारत और अमेरिका के विचार एक जैसे हैं और दोनों का रुख एक समान है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। अमेरिका और भारत अपने समन्वित कूटनीतिक कार्यों से चीन का मुकाबला करने के लिए अधिक मुखर और सहयोगी दृष्टिकोण का मंच तैयार कर रहे हैं।

अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में तथा अमेरिकी संसद द्वारा पारित रिजॉल्व तिब्बत ऐक्ट को, जो तिब्बती लोगों को पूर्ण समर्थन देने का वादा करता है, अपनाने के बाद अमेरिकी संसद का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत के धर्मशाला में दलाई लामा से मिला, जिससे चीन बुरी तरह भड़क गया। रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइकल मैककॉर्ल के नेतृत्व में सात सदस्यीय उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने रिजॉल्व तिब्बत ऐक्ट के महत्व पर चर्चा की, जिसे राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जो तिब्बती लोगों के अधिकारों के प्रबल पैरोकार हैं।

के एस तोमर
राजनीतिक विश्लेषक

इसी से संबंधित घटनाक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी और देश में हुए लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता और व्यापकता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपना संदेश पोस्ट करते हुए लिखा कि 'प्रतिनिधिमंडल में शामिल अमेरिकी संसद के मित्रों के साथ विचारों का बहुत अच्छा आदान-प्रदान हुआ।' उन्होंने आगे कहा कि वह 'भारत-अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में मजबूत द्विदलीय समर्थन' को 'गहराई से' महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट में दलाई लामा के साथ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बैठक का उल्लेख नहीं है। रणनीतिक दृष्टि से इसे गुप्त रखा गया है। निर्वासित तिब्बती सरकार की मेजबानी करने वाले भारत का तिब्बत के साथ एक अनूठा संबंध है।

भारत सरकार अक्सर तिब्बती मुद्दे के प्रति अपने समर्थन और चीन के साथ व्यापक रणनीतिक व आर्थिक संबंधों के बीच संतुलन बनाते हुए कदम उठाती रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की धर्मशाला यात्रा के तुरंत बाद इस बैठक का समय चीन की आक्रामक नीतियों का मुकाबला करने में साझा मूल्यों और आपसी हितों को रेखांकित करने के लिए एक समन्वित कूटनीतिक प्रयास का संकेत देता है। जैसी की उम्मीद थी, चीनी दूतावास की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, जिसमें अमेरिका को गलत संदेश देने से बचने की चेतावनी दी गई। चीनी मिशन ने एक्स पर कहा, 'हम अमेरिकी पक्ष से आग्रह करते हैं कि वह दलाई समूह के चीन विरोधी अलगाववादी प्रकृति को पूरी तरह पहचाने, शिजांग मुद्दे पर अमेरिका ने चीन से जो वादा किया था, उसका सम्मान करे और दुनिया को गलत संदेश देना बंद करे।'

तिब्बती इतिहास एवं संस्कृति को कमजोर करने के लिए चीन तिब्बत को शिजांग कहता है, जिसे अक्तूबर, 1950 में उसने जबरन हड़प लिया था। दलाई लामा धर्मशाला में निर्वासित रहकर तिब्बती लोगों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। इन बैठकों पर चीनी प्रतिक्रिया संभवतः बहुआयामी होगी। कूटनीतिक मोर्चे पर बीजिंग वाशिंगटन और नई दिल्ली के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज कर सकता है। वह तिब्बत पर चीनी रुख को आंतरिक मामला बताते हुए उसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की निंदा करेगा। हालांकि, व्यापक रणनीतिक निहितार्थ चीन के क्षेत्रीय कूटनीतिक दृष्टिकोण को फिर से निर्धारित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि तिब्बत के बारे में भारत और अमेरिका के विचार एक जैसे हैं और दोनों का रुख एक समान है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि चीन ने 1962 में भारत के साथ धोखा किया, जिसे 2020 में दोहराया गया, जब लद्दाख में टकराव हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजिंग के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए गंभीर पहल की थी, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला है।

इन बैठकों से पता चलता है कि अमेरिकी और भारतीय हितों के मेल से एशिया में एक नई भू-राजनीतिक परिदृश्य का विकास हो रहा है। दोनों देश खासकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और आक्रामक व्यवहार के प्रति समान रूप से आशंकित हैं। अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए अमेरिका और भारत चीनी महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता जता रहे हैं। बदले में चीन अपने गठजोड़ को मजबूत करने और क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने पर जोर दे सकता है। इसके तहत वह पाकिस्तान के साथ संबंधों को गहरा कर सकता है, अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ भागीदारी बढ़ा सकता है और रणनीतिक पैठ जमाने के लिए अपनी बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं में तेजी ला सकता है। इसके अलावा, चीन भारत के साथ विवादित सीमाओं पर अपनी सैन्य स्थिति को बढ़ा सकता है, खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के विवादास्पद क्षेत्रों में, ताकि अपने क्षेत्रीय दावों को पुख्ता किया जा सके।

तात्कालिक रणनीतिक गणनाओं से परे, ये बैठकें लोकतांत्रिक मूल्यों और तानाशाही शासन के बीच व्यापक वैचारिक प्रतिस्पर्धा को भी उजागर करती हैं। अहिंसक प्रतिरोध और आध्यात्मिक नेतृत्व के प्रतीक दलाई लामा उन मूल्यों के प्रतीक हैं, जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों की वैश्विक पैरोकारी करते हैं। उनके साथ जुड़कर, अमेरिका और भारत इन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ, चीन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को बचाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग में चीनी गतिविधियों पर बढ़ती वैश्विक निगरानी बीजिंग को रक्षात्मक स्थिति में ले आई है। वैश्विक प्रभाव की लड़ाई में, सॉफ्ट पावर और नैतिक अधिकार तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। धर्मशाला और दिल्ली की बैठकें अमेरिका और भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे उन्हें मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों का अगुआ माना जाता है।

जैसे-जैसे एशिया में भू-राजनीतिक बिसात जटिल होती जाएगी, कूटनीति और प्रतिरोध के बीच का अंतर-संबंध महत्वपूर्ण होता जाएगा। अमेरिका और भारत, अपने समन्वित कूटनीतिक कार्यों से, चीन का मुकाबला करने के लिए अधिक मुखर और सहयोगी दृष्टिकोण का मंच तैयार कर रहे हैं। इसमें न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना शामिल है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों के साथ व्यापक गठजोड़ को बढ़ावा देना भी शामिल है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

सुकरात

खुशी हमेशा हमारी गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य होती है, इसलिए यह बिना शर्त अच्छी है। खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि चीजों का उपयोग कैसे किया जाता है।

पैसा तभी अच्छा है, जब बुद्धिमानों के हाथों में हो

खुशी की कुंजी शरीर से ध्यान हटाकर आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करने में छिपी है। अनैतिक जीवन की तुलना में नैतिक जीवन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि यह खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। खुशी सद्गुण, न्याय और मानव अस्तित्व के अंतिम अर्थ जैसी अवधारणाओं से भी जुड़ी है। खुशी हमेशा हमारी गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य होती है, इसलिए यह बिना शर्त अच्छी है। खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि चीजों का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पैसे का सही तरीके से उपयोग करेगा, जबकि एक अज्ञानी व्यक्ति पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा और फिर उसका अंत पहले से भी बदतर होगा। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि पैसा अपने आप में किसी को खुश कर सकता है। पैसा केवल तभी अच्छा है, जब यह बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों में हो। इसी तर्क को किसी भी बाहरी अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कोई भी संपत्ति, कोई भी गुण, यहां तक कि अच्छा दिखना या योग्यता।

हम सभी खुश रहना चाहते हैं, और हम चीजों के अच्छे उपयोग के कारण खुश होते हैं। इसमें ज्ञान ही वह चीज है, जो उपयोग की इस अच्छाई की समझ और सौभाग्य प्रदान करती है। इसलिए हर व्यक्ति को हर तरह से इसके लिए खुद को तैयार करना चाहिए यानी जितना संभव हो, उतना बुद्धिमान बनना। खुशी की कुंजी किसी व्यक्ति द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं में नहीं पाई जाती, बल्कि यह व्यक्ति के अपने भीतर ही मौजूद है, जो जीवन को एक दिशा देती है और ध्यान केंद्रित करती है। खुशी केवल हमारी इच्छाओं की संतुष्टि में निहित है। यह निर्धारित करने के लिए कि कौन-सी इच्छाएं संतुष्ट करने योग्य हैं? हमें अपनी आलोचनात्मक और चिंतनशील बुद्धि का उपयोग करना होगा। हमें मानव स्वभाव की समझ तक पहुंचना होगा और यह पता लगाना होगा कि मनुष्य में सबसे अच्छा क्या है, कौन-सी इच्छाएं परस्पर प्रबल होती हैं और कौन-सी हमें समग्र उद्देश्य और अच्छी तरह से काम करने की भावना प्राप्त करने से रोकती हैं। सभी लोग स्वाभाविक रूप से खुशी चाहते हैं। इसलिए हम सभी को न्यायपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। शरीर में स्वास्थ्य और आत्मा में न्याय के बीच एक समानता है। स्वास्थ्य शरीर के विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य के अलावा और कुछ नहीं है। इसी तरह न्याय भी एक समान प्रकार का सामंजस्य है, लेकिन यह आत्मा के विभिन्न भागों के बीच है। दूसरी ओर अन्याय आत्मा के विभिन्न भागों के बीच एक गृहयुद्ध की तरह है, जिसमें एक विद्रोह मौजूद रहता है और नियंत्रण शक्ति के रूप में तर्क को हड़प लेता है। इसके विपरीत, न्यायी आत्मा वह है, जिसमें मानसिक सामंजस्य होता है।

सदाचारी जीवन

सूत्र

न्यायी व्यक्ति पर कुछ भी फेंक दें, लेकिन वह कभी भी अपना आंतरिक संयम नहीं खोता और जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद शांति और स्थिरता बनाए रखता है। यही हमारे भीतर छिपी सच्ची खुशी है। खुशी सदाचार से भी जुड़ी है। अधार्मिक जीवन जीने की तुलना में सदाचारी जीवन जीने से कहीं ज्यादा खुशी का अनुभव होता है।

दूसरा पहलू

ब्लैक होल एक बेहद विशाल परिधि में फैली वह जगह है, जो अमूमन तब बनती है, जब किसी तारे की उम्र पूरी हो जाती है।

अगर आप ब्लैक होल में कूद जाएं

आपने टाइम मशीन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। वही टाइम मशीन, जिसके बारे में यह कल्पना की जाती है कि वह हमें अतीत या भविष्य में ले जा सकती है। ब्लैक होल दरअसल ऐसी ही एक प्राकृतिक टाइम मशीन है, जिसके माध्यम से अतीत और भविष्य की यात्रा की जा सकती है। दरअसल, ब्लैक होल एक बेहद विशाल परिधि में फैली वह जगह है, जो अमूमन तब बनती है, जब किसी तारे की उम्र पूरी हो जाती है और वह ढह जाता है। ग्रहों व तारों की तरह ब्लैक होल के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है।

सैम बरोन

भौतिक विज्ञान का एक सामान्य नियम है कि कोई वस्तु जितनी विशाल होगी, उसका गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र उतना ही शक्तिशाली होगा। इसलिए हम रॉकेट बनाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत तेज यात्रा करनी होती है। विज्ञान अब तक जो सबसे तेज गति से चलने वाली चीज ढूंढ पाया है, वह प्रकाश है। लेकिन ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं पाता। अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत बताता है कि जब कोई बहुत विशाल वस्तु अंतरिक्ष में स्थित होती है, तो उसके चारों ओर की जगह उतनी ही ज्यादा खिंची या मुड़ी होती है। कोई भी विशाल ग्रह अंतरिक्ष में एक तरह की घाटी बनाता है। जब कोई भी वस्तु इनके नजदीक जाती है, तो वह घाटी में गिर जाती है। यही वजह है कि जब आप ब्लैक होल जैसी किसी विशाल वस्तु के एकदम पास आते हैं, तो उसकी ओर गिर जाते हैं। यही वजह है कि प्रकाश ब्लैक होल से बच नहीं पाता। वह बिंदु या घटना जब यह इतनी तीव्र हो जाती है कि प्रकाश भी न बच पाए, 'क्षितिज' (Horizon) कहलाता है।

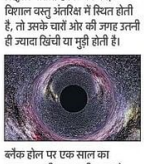

ब्लैक होल पर एक साल का मतलब पृथ्वी पर अस्सी साल हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ब्लैक होल के क्षितिज के नजदीक पहुंचने के लिए जो अंतरिक्ष यान चाहिए, वह अब तक बना नहीं है।

अंतरिक्ष की तरह समय का भी विस्तार है। विशाल वस्तु के पास रखी घड़ी, छोटी वस्तु के पास रखी घड़ी की तुलना में धीमी चलेगी। ब्लैक होल के पास रखी घड़ी पृथ्वी पर मौजूद घड़ी की तुलना में बहुत धीमी गति से चलेगी। ब्लैक होल पर एक साल का मतलब पृथ्वी पर अस्सी साल हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ब्लैक होल के क्षितिज के नजदीक पहुंचने के लिए जो अंतरिक्ष यान चाहिए, वह अब तक बना नहीं है। दूसरी बात, क्षितिज तक पहुंचने और वहां से लौटने के लिए जरूरी है कि आपकी गति प्रकाश से तेज हो। जब आप क्षितिज से गुजरेंगे, तो आप नुडल की तरह पतले हो चुके होंगे या शायद शून्य में विचर रहे परमाणुओं की एक शृंखला मात्र रह जाएंगे। तो अगली बार जब नुडल्स खाइएगा, तब ब्लैक होल के बारे में जरूर सोचिएगा। - कन्वर्सेशन से

आंकड़े

तंबाकू की जकड़ में युवा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 14 से 49 वर्ष तक की उम्र के लगभग सभी धर्मों के लोग तंबाकू का सेवन करते हैं।

सिख 12.2% और अन्य धर्मों के लोग 45.8% तक तंबाकू का सेवन करते हैं। स्रोत : NFHS-5

रत्नाकर ने जब अपने परिजनों से पूछा कि क्या तुम सब मेरे पाप के भागीदार बनोगे, तो सभी ने मना कर दिया। वह नारद जी के पास पहुंचे और रोने लगे।

नारद ने वाल्मीकि को दिया मंत्र

अंतर्यात्रा
संकलित

महर्षि वाल्मीकि का जन्म अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन डाकुओं के साथ रहने से वह लूट और हत्याएं करने लगे। उनका पूर्व का नाम रत्नाकर था। एक दिन जंगल में नारद जी जा रहे थे। रत्नाकर उनके ऊपर झपट पड़े और कहा, लाओ तुम्हारे पास क्या है? नारद जी बोल, मेरे पास तो यह वीणा है। रत्नाकर ने पूछा, इस वीणा का क्या करते हो, बजाकर दिखाओ? नारद जी ने मधुर स्वर में वीणा बजाकर भगवान के नाम का कीर्तन किया। इससे उसका दिल पसीजा। नारद ने कहा कि जीव हिंसा से बड़ा पाप लगता है।

रत्नाकर बोले-हमारा परिवार बड़ा है। उनका भरण-पोषण करना होता है। नारद ने कहा कि अपने परिवार वालों से पूछो कि क्या वे तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे। वह परिजनों के पास पहुंचे, तो सभी ने इन्कार करते हुए कहा कि हमारे लिए भोजन लाना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन तुम्हारा पाप हम अपने ऊपर नहीं ले सकते।

लौटकर वह नारद जी के पास पहुंचे और रोने लगे। नारद जी ने शांत करते हुए कहा कि तुम 'राम' नाम के मंत्र का जाप करो। तुम्हारे सारे पाप धुल जएंगे, लेकिन रत्नाकर ने कहा-भगवन! मुझसे राम नाम का जाप नहीं हो रहा है। कहा कि कुछ नहीं 'मरा-मरा' बोलो। रत्नाकर तपस्या में लग गए। धीरे-धीरे 'मरा-मरा' की जगह 'राम-राम' का जाप होने लगा। उनके ऊपर दीमकों ने बामी बना ली। इसी से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। बाद में वाल्मीकि ने *रामायण* की रचना की।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 2 अप्रैल, 1953

बर्मा के मामले में नेहरू की गहरी दिलचस्पी

बर्मा के मामले में नेहरू की गहरी दिलचस्पी
क्या प्रधानमंत्री ने चीनी सरकार 'बेवकूफ' बना रही है?
नेहरू ने कहा कि भारत सरकार ने राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा अमेरिका, ब्रिटेन व कई अन्य देशों की सरकारों से बर्मा (अब म्यांमार) में कुमिंगतांग (राष्ट्रवादी चीनी) सेनाओं की उपस्थिति के संबंध में बातचीत की है।

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत सरकार ने राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा अमेरिका, ब्रिटेन व कई अन्य देशों की सरकारों से बर्मा (अब म्यांमार) में कुमिंगतांग (राष्ट्रवादी चीनी) सेनाओं की उपस्थिति के संबंध में बातचीत की है।

पृथ्वी में छिपी एक नई दुनिया

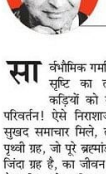

वैज्ञानिकों ने दक्षिण अमेरिका के अटाकामा मरुस्थल की तपती रेत के नीचे छिपे हुए जीवमंडल को उजागर किया है।

वीर सिंह | शोध

सार्वभौमिक गर्माहट, नित नए रिकॉर्ड बनाता सृष्टि का तापक्रम, और जीवन की कड़ियों को तोड़ने पर उतारू जलवायु परिवर्तन! ऐसे निराशाजनक भू-परिदृश्य में कोई सुखद समाचार मिले, तो मन हर्षित हो जाता है। पृथ्वी ग्रह, जो पूरे ब्रह्मांड में अब तक एकमात्र ज्ञात जिंदा ग्रह है, का जीवन के प्रति एक गहरा अनुराग है। जीवन के प्रति गहरी आत्मीयता संजोए और जीवन को निरंतर पोषित करती पृथ्वी का एक दिव्य दर्शन पृथ्वी पर सबसे शुष्क और जीव रहित अटाकामा रेगिस्तान के नीचे छिपे एक जीवमंडल की हाल में हुई एक खोज से हुआ है।

एक अभूतपूर्व खोज में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे विकट पर्यावरण और जीवन संभावनाओं को ठेंगा दिखाने वाली चरम पर पहुंची जलवायु वाले अटाकामा रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे छिपे हुए जीवमंडल को उजागर किया है। अनंत

काल से जीवन से रहित माना जाने वाला अटाकामा अब नीचे की गहराइयों में पनप रहे सूक्ष्मजीवी जीवन की एक आश्चर्यजनक शृंखला को प्रकट करता है।

अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए 1000 किलोमीटर तक विस्तार लिए हुए है। इसकी शुष्कतम जलवायु, जिसमें वस्तुतः नहीं के बराबर (मात्र 1 से 3 मिलीलीटर प्रतिवर्ष) वर्षा होती है, जो जीवन प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त नहीं है और अत्यधिक तापमान का उतार-चढ़ाव होता है, ने वैज्ञानिकों को इसकी तुलना मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली स्थितियों से करने के लिए प्रेरित किया है। इसकी दुर्गम सतह के उपरांत भी शोधकर्ताओं को लंबे समय से संदेह था कि ऊपर की कठोरता से सुरक्षित होकर निचली सतह पर जीवन बना रह सकता है।

वैज्ञानिकों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह के नेतृत्व में हाल के अभियानों ने इन संदेहों की पुष्टि की है, क्योंकि उन्होंने रेगिस्तान की मिट्टी और चट्टानों की गहराई में खोज की है। डीएनए अनुक्रमण और समस्थानिक विश्लेषण सहित अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने इस असंभावित आवास में पनप रहे सूक्ष्मजीवों के एक विविध समुदाय की पहचान की है।

परियोजना की प्रमुख शोधकर्ता डॉ. ऐलेना रोड्रिग्ज इस खोज को 'उल्लेखनीय रहस्योद्घाटन' के रूप में वर्णित करती हैं। वह कहती हैं कि अटाकामा मरुस्थल को लंबे समय से रेत और चट्टान का एक बेजान विस्तार माना जाता रहा है, लेकिन हमारे निष्कर्ष इस धारणा को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। सतह के नीचे, जहां स्थितियां अधिक स्थिर हैं, हमने सूक्ष्मजीव जीवन के एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र का सामना किया है। खोजा गया एक नया जीवमंडल अपने भूमिगत पर्यावरण की चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ है। बैक्टीरिया, आर्किया और कवक सहित इन सूक्ष्मजीवों ने इस कठोर परिदृश्य में जीवित रहने के लिए सरल रणनीतियां विकसित की हैं। इनमें से कुछ खनिजों से भोजन करते हैं, जबकि अन्य ऊर्जा को लिए रासायनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर रहते हैं और इस प्रकार दुनिया से छिपकर अपने लिए एक अनूठा आश्रय बनाते हैं। यह अद्भुत खोज हमारे मन में जीवन के प्रति सम्मान और पवित्रता के भावों का बीजारोपण करती है।

इसके अतिरिक्त, अटाकामा मरुस्थल में खोजे गए सूक्ष्मजीव समुदाय मंगल जैसे अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना का सुराग दे सकते हैं। मंगल ग्रह की सतह से अपनी समानता के साथ अटाकामा मरुस्थल चरम वातावरण में जीवन की सीमाओं का अध्ययन करने और अलौकिक जीवन के लिए हमारी खोज को परिष्कृत करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर सकता है।

जैस-जैसे शोधकर्ता अटाकामा मरुस्थल और पृथ्वी पर अन्य चरम वातावरणों की गहराई का पता लगाना जारी रखते हैं, वे निश्चित रूप से और भी अधिक आश्चर्यों को उजागर करेंगे। प्रत्येक नई खोज हमें जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में इसकी क्षमता के रहस्यों को उजागर करने के समीप लाती है। अटाकामा ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन की अनंत संभावनाओं के विकास की खिड़की खोलता है।

दैनिक जागरण
हर इंसान इस पृथ्वी पर ईश्वर का मेहमान है

अनावश्यक आपत्ति

नई लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा, उससे मोदी सरकार के एजेंडे की ही झलक मिली। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि ऐसे अवसरों पर राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की रूपरेखा को ही रेखांकित करता है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से यही स्पष्ट होता है कि यह सरकार पहले की तरह ही कार्य करेगी और उन कामों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देगी, जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री पिछले कुछ समय से लगातार करते आ रहे हैं। इस सबके बाद भी वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि अपने तीसरे कार्यकाल में उन्हें संसद के भीतर और बाहर विपक्ष के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ेगा। इसका एक बड़ा कारण उसके संख्याबल में वृद्धि होना है। संख्याबल में वृद्धि के चलते विपक्ष को जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल हुआ है, वहीं दूसरी ओर उसका मनोबल भी बढ़ा है। बीते तीन-चार दिनों में संसद में जो कुछ हुआ, उससे विपक्ष के बढ़े हुए मनोबल का ही पता चलता है। विपक्ष का उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन उचित यह होगा कि वह विरोध के लिए विरोध वाले रवैये का परित्याग करे। इसके स्थान पर उसे रचनात्मक विरोध का परिचय देना चाहिए। दुर्भाग्य से फिलहाल इसके आसार कम ही हैं और इसका संकेत राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ बिंदुओं पर विपक्षी नेताओं की अनावश्यक आपत्ति से मिलता है। यह कोई नई-अनोखी या गोपनीय बात नहीं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की ओर से तैयार किया जाता है। आखिर ऐसे में यह कहने का क्या मतलब कि उनका अभिभाषण तो सरकारी भाषण है। ऐसा तो होता ही है।

यह आश्चर्यजनक है कि विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के उन बिंदुओं पर भी हंगामा किया, जिनका कोई औचित्य नहीं था। जब राष्ट्रपति ने प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ठोस उपाय करने की जरूरत जताई तो विपक्ष को यह रास नहीं आया। क्या यह एक तथ्य नहीं कि बीते पांच वर्षों में केंद्रीय स्तर के साथ ही राज्य स्तर की भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं? विपक्ष तब भी आगे से बाहर होता हुआ दिखा, जब राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आपातकाल के काले कारनामों को याद किया। आखिर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस आपातकाल के जिक्र मात्र से क्यों भड़क जा रही है? कांग्रेस नेता आपातकाल का उल्लेख भर किए जाने से जिस तरह बिदक रहे हैं, उससे तो वे यही साबित कर रहे हैं कि आपातकाल का स्मरण किया जाना क्यों आश्चर्यक है। यह हैरानी ही नहीं, चिंता का भी विषय है कि कांग्रेस को आपातकाल के स्मरण पर भी आपत्ति है। बेहतर होगा कि सरकार का विरोध करते समय विपक्ष तनिक तार्किक रवैया अपनाए।

बढ़ानी होगी चौकसी

बिहार में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ और पाकिस्तानी अपराधियों की बढ़ती गतिविधियां चिंताजनक हैं। गत दिवस पुलिस ने पटना से दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम चंपारण के रहने वाले दोनों बदमाश पाकिस्तानी साइबर अपराधियों के संपर्क में थे। इन दोनों के अलावा राज्य के कई और युवक पाकिस्तानी अपराधियों के संपर्क में हो सकते हैं। संभव है कि जिस तरह सलमान खान पर हमला करने वाले युवकों की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम चंपारण से ही गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के संपर्क में रहने वाले आधा दर्जन युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसी तरह इन साइबर अपराधियों के स्थानीय संपर्क सूत्र को भी खंगाला जाना चाहिए। प्रदेश में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन नए-नए मामले दर्ज हो रहे हैं। ये अपराधी कहीं से बैठकर लोगों को ठगी का शिकार बना लेते हैं। इनमें पाकिस्तानी मोबाइल नंबर का उपयोग अधिक हो रहा है। इसके अलावा देश की सुरक्षा से जुड़ी दस्तावेज को हनी ट्रैप के माध्यम से चुराने का मामला भी पकड़ में आया है। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर के कटरा निबंधन कार्यालय में कार्यरत एक लिपिक ने आइएसआइ की महिला हैंडलर के हनी ट्रैप में फंसकर उसे रक्षा से जुड़ा दस्तावेज उपलब्ध करा दिया था। रवि यहां लिपिक बनने से पहले चेन्नई के अवाडी स्थित रक्षा मंत्रालय के भारी वाहन कारखाने में क्लर्क था। कंप्यूटर पर ड्यूटी के दौरान मिलने वाली गोपनीय दस्तावेज वह आइएसआइ एजेंट को बेच देता था। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अलर्ट किया है और ऐसे मामलों की सूची मांगी है। बिहार में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए साइबर थाने खोले गए हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) भी मामलों की निगरानी करती है, लेकिन आम लोगों को भी सजग रहना होगा। संदिग्ध गतिविधियों वाले लोगों की जानकारी पुलिस को तत्काल उपलब्ध करानी चाहिए।

तिब्बत की आवाज बने भारत

शंकर शरण

जिस मुद्दे पर भारत ने चीन से धोखा खाया, उसे यानी तिब्बत को उठाकर ही सही मार्ग पाया जा सकता है

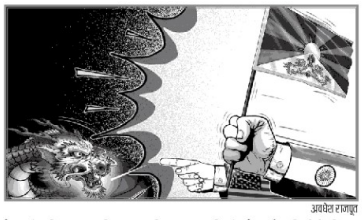

अवधेश राजपूत

अमेरिकी संसदों का एक दल जिस तरह दलाई लामा से धर्मशाला आकर मिला, वह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दल के सांसदों में नैंसी पेलोसी भी थीं, जिन्होंने अमेरिकी संसद में 'रिसाल्व तिब्बत एक्ट' का विधेयक रखा है। इसमें तिब्बत समस्या के समाधान के लिए चीन पर दबाव डालने की सिफारिश है। इस विधेयक पर अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ही जाने से चीन पर तिब्बतियों से बातचीत करने का दबाव बनने की अमेरिकी गंभीरता झलकेगी। इसका प्रभाव दुनिया के अनेक देशों पर भी पड़ सकेगा। इन देशों में सबसे महत्वपूर्ण भारत है। उल्लेखनीय केवल यह नहीं कि भारत ने अमेरिकी सांसदों के दल को धर्मशाला आकर दलाई लामा से मुलाकात करने की अनुमति दी, बल्कि इस दल से प्रधानमंत्री मोदी ने भी भेंट की। डोकलाम और गलवन घाटी पर भारत-चीन तनाव के संदर्भ में भी इसका संकेत स्पष्ट है। यदि भारत भी कूटनीति में चीन की तरह यथार्थवादी कदम उठाए तो आपसी संबंध सुधार की संभावना बढ़ेगी। केवल सदिच्छा और सांकेतिक बातों से भारत को आज तक कुछ लाभ नहीं हुआ। वस्तुतः तिब्बत ही भारत-चीन संबंधों की बीच की कड़ी है। इसकी अनदेखी से आपसी विश्वास नहीं बन सकेगा।

यहां स्मरणीय है कि बीजिंग में 1954 में हुआ पंचशील समझौता भारत-तिब्बत पर ही था। इस समझौते का शीर्षक ही है: ''चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और संबंध के बारे में।'' छह अनुच्छेदों के इस संक्षिप्त समझौते में कुल नौ बार तिब्बत का नाम आया है। इसमें से पांच अनुच्छेदों में केवल इसके वर्णन हैं कि भारत-तिब्बत संबंध पूर्ववत चलते रहेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से सौ-पचास साल कुछ नहीं होते। 1951 तक तिब्बत स्वतंत्र देश था। मार्च 1947 में दिल्ली में 'एशियन रिलेशंस कांफ्रेंस' में तिब्बत और चीन, दोनों ने स्वतंत्र देशों की तरह हिस्सा लिया था। 1914 में शिमला में चीन, तिब्बत और भारत ने आपसी सीमांकन समझौता भी किया था। यदि चीन 1890 के दस्तावेज का हवाला देकर डोकलाम को अपना बताता है, तो 1914 के दस्तावेज के अनुसार तिब्बत भी स्वतंत्र देश है। ऐसे तथ्य उठाकर ही भारत, चीन और तिब्बत, तीनों के बीच पहले की तरह परस्परता का संबंध बनने का मार्ग मिल सकता है। यह ठीक है कि 1949 में भारत से भूल हुई जब उसने चीनी कम्युनिस्टों को तिब्बत हड़पने दिया। उसके एवज में चीन ने भारत और तिब्बत को संतुष्ट करने के लिए पंचशील का उपाय किया। उसका सार यही था कि तिब्बत और भारत के सांस्कृतिक, व्यापारिक, सामाजिक संबंध पहले जैसे चलते रहेंगे-बिना किसी पासपोर्ट, वीजा या परमिट आदि के।

यह ऐतिहासिक सत्य है कि भारत और तिब्बत के संबंध सदियों से खुले और पारस्परिक थे, जिसमें चीन का कोई अवरोध न था। जब चीनी नेता पंचशील समझौते का हवाला देते हैं, तो भारतीय नेताओं को कहना चाहिए कि उसके अनुच्छेद दो और पांच के अनुरूप तिब्बती एवं भारतीय तीर्थयात्रियों की बेरोक-टोक यात्राएं पुनःस्थापित की जाएं। वस्तुतः न्याय और व्यावहारिकता, दोनों का तकाजा है कि पंचशील समझौते के सभी छह अनुच्छेद लागू किए जाएं, अन्यथा तिब्बत और उसकी सहायता के लिए भारत समेत दुनिया के अन्य उदार देश उसी तरह स्वतंत्र हैं, जैसे अन्य देश किसी पीड़ित देश की मदद के लिए होते हैं। निर्मल वर्मा ने तिब्बत को 'संसार का अंतिम उपनिवेश' बताया था। भारत और तिब्बत को अपनी साझी चिंताओं और संस्कृतिक जरूरतों पर बोलने का पूरा अधिकार है। यही पूरे मामले को सुलझाने का सूत्र है, पर अधिकांश नेता और बुद्धिजीवी 'तिब्बत रीजन आफ चाइना' को शब्दावली में सदैव चाइना पकड़ते हैं और तिब्बत भूल जाते हैं। वास्तव में होना उलटा चाहिए। सदैव तिब्बत का नाम लें और चीन को टोकें। भारत का पड़ोसी पहले तिब्बत है। उसके पार चीन है। पंचशील समझौता होने पर कई पत्र-पत्रिकाओं में खबर का शीर्षक था-भारत-तिब्बत समझौता। इसके दो-तीन दशक बाद भी दुनिया भर के नक्शों में तिब्बत अलग देश ही रहा। दुर्भाग्यवश भारतीय बुद्धिजीवी और नेता कई गंभीर चीजों का नाम लेते हैं, पर उसके अर्थ पर ध्यान नहीं देते, जबकि चीन यथार्थवादी होने के कारण तिब्बत और भारत दोनों के अधिकार से अवगत है। इसीलिए वह दलाई लामा पर सावधान रहता है। उनसे देसी-विदेशी नेताओं के मिलने-जुलने का विरोध करता है, जबकि भारत अपने कर्तव्य से चूक जाता है। यह विचित्र है कि जिस तिब्बत को लेकर भारत का समझौता बीजिंग से हुआ था, उस तिब्बत की बात भारत ही नहीं करता।

चीन द्वारा तिब्बत पर हमले के बाद संपूर्ण विश्व ने पहले भारत की ओर ही देखा था, क्योंकि उससे संबंधित प्रभावित होने वाला देश भारत था। भारत द्वारा चीन का समर्थन करते रहने से ही दुनिया चुप रही। वरना तब तक कम्युनिस्ट चीन महाशक्ति क्या, मान्यता प्राप्त देश तक नहीं था। संयुक्त राष्ट्र में भी 1971 तक फारमोसा (ताइवान) को मान्यता थी। अमेरिका ने 1978 तक कम्युनिस्ट चीन से कूटनीतिक संबंध तक नहीं बनाए थे। यदि तिब्बत पर भारत आवाज उठाता, तो चीन मनमानी नहीं कर सकता था। वह भूल सुधरना भारत का अनिवार्य कर्तव्य है। उस पर चुप्पी रखने से भारत की हानि होती है। यदि भारत ने साहजता से तिब्बत का मुद्दा उठाया होता, तो चीन को भारत के साथ सद्भाव बनाने की चिंता होती। तिब्बत की स्थिति भी सुधरती। अभी तिब्बत असहाय लगता है, पर यदि भारत ने इसे विश्व-मंच पर उठा दिया, तो ऐसा नहीं रहेगा। चीनी सत्ता ने अपने देश में तानाशाही को औजार बनाया है, तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भारत का साधन बन सकता है। तिब्बतियों की वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अभियान चलाने में सहायता देना भारत के हाथ में है। ऐसा न करना स्वयं भारत की नैतिक प्रतिज्ञा के विरुद्ध है। विविध सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन, गैर राजनीतिक लोग भी तिब्बत पर आवाज उठा सकते हैं।

भारत-चीन संबंध और तिब्बत की स्वायत्तता का आपस में जुड़ाव है। वर्तमान स्थिति स्थाई नहीं है। चूंकि किसी भी नए घटनाक्रम से हालत बदल सकते हैं, अतः सभी को अपना धर्म निभाना चाहिए। इससे ही वांछित बदलाव होंगे।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

हार कर भी खुशी मनाती कांग्रेस

अवधेश कुमार

कांग्रेस को भाजपा की सीटें घटने पर आनंदित होने के बजाय अपनी हार का मूल्यांकन करना चाहिए

गत दिनों राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर रायबरेली से सांसद रहने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम से कांग्रेस के अंदर यह विश्वास पैदा हुआ है कि अगर राहुल गांधी ने वहां ध्यान दिया तो अगले आम चुनाव में पार्टी की स्थिति बेहतर हो सकती है और लोकसभा में अंकगणित बदल सकता है। क्या इस चुनाव परिणाम के आधार पर माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में कांग्रेस के दिन वापस लौट सकते हैं? चूंकि भाजपा की सीटें घटीं और कांग्रेस तथा कुछ विपक्षी दलों की बढ़ीं, इसलिए उनके अंदर उम्मीद पैदा हुई है कि फिर से हमारा उत्थान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस एवं विपक्ष के अन्य दल यह न भूलें कि कांग्रेस 1991 के बाद केवल 2009 में ही 200 का आंकड़ा पार कर 206 की संख्या तक पहुंची थी। इसमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त 21 सीटों का बड़ा योगदान था। कांग्रेस का यह संकट आज का नहीं है। 1989 में भी उसे सिर्फ 197 लोकसभा सीटों पर ही विजय मिली थी। 1991 में भी 232 सीटें तब मिली थीं, जब राजीव गांधी की हत्या से कांग्रेस को सहानुभूति मिली थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वह 200 के आंकड़े से नीचे ही होतीं। 1996 में उसे 140, 1998 में 141, 1999 में 114 तथा 2004 में 145 सीटें मिलीं। 2009 को छोड़ दें तो 2014 में 44, 2019 में 52 और 2024 में 99 सीटें मिलीं। इस तरह पिछले 35 वर्षों में कांग्रेस ने लोकसभा में केवल दो बार 200 का आंकड़ा पार किया। 2009 में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने सपा को छोड़ कांग्रेस के लिए मतदान किया और इस कारण उसकी सीटें बढ़ीं।

2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार का गठन इस कारण हुआ, क्योंकि भाजपा को 138 सीटें मिलीं और उसके विरोधी दलों ने कांग्रेस के इर्द-गिर्द मोर्चा बना लिया। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा उस तरह प्रखर राजनीतिक पार्टी के रूप में चुनाव में नहीं दिखी, जिससे उसका व्यापक समर्थन वर्ग खड़ा हो सके। नरेन्द्र मोदी के आते ही 2014 में पूरी स्थिति वास्तविकता पर लौट आई। एक समय कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। बाद में जनाधार के स्तर पर कांग्रेस ने विचार, व्यवहार एवं व्यक्तित्व यानी नीति, रणनीति और नेता के स्तर पर ऐसा जनाकर्षक परिवर्तन नहीं किया, जो फिर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आम भारतीय को उसका प्रतिबद्ध समर्थक बना दे। राहुल गांधी 2004 से संसद हैं और उत्तर प्रदेश में उसके पहले से सक्रिय हैं। प्रियंका वाड्रा भी लगातार सक्रिय हैं। बावजूद इसके कांग्रेस प्रदेश में अपने पैरों पर आज तक खड़ी नहीं हो सकी है। प्रियंका वाड्रा के कांग्रेस महासचिव बनने तथा उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने पर 2019 में कांग्रेस से केवल सोनिया गांधी रायबरेली से निर्वाचित हुई थीं। दक्षिण में केरल में भी भाजपा के कमजोर होने के कारण कांग्रेस नेतृत्व या फिर वाम मोर्चा वाले गठबंधन के चलते ही वहां की ज्यादातर सीटें उसे मिलती रहीं हैं। आंध्र में कांग्रेस नहीं है। तमिलनाडु में द्रमुक गठबंधन के कारण उसे सीटें मिलती हैं। कर्नाटक में उसकी सरकार रहते हुए भी 1999 को छोड़कर लोकसभा चुनावों में लगातार भाजपा को ज्यादा सीटें मिलती रही हैं। तेलंगाना में अवश्य वह अपना आधार कुछ हद तक प्राप्त कर पाई है। ऐसे में भले राहुल गांधी उत्तर प्रदेश और प्रियंका वाड्रा केरल चली जाएं, इससे कांग्रेस के व्यापक विस्तार की संभावना दिखाई नहीं देती है।

भाजपा की सीटें घटना उसके स्वयं के लिए गंभीर चिंता का विषय है। चूंकि इसमें बड़ी भूमिका उसके कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और प्रतिबद्ध समर्थकों की है, जिन्होंने या तो उदासीनता बरती, या बिल्कुल काम नहीं किया या विरोध कर दिया। कांग्रेस भाजपा को ज्यादा नुकसान पहुंचाने या कमजोर करने में वहीं सफल हुई, जहां वह गठबंधन में थी। जैसे- उत्तर प्रदेश में सपा के साथ उसके गठबंधन के कारण भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बनी। गठबंधन में भी कांग्रेस 17 सीटों पर ही लड़ पाई। महाराष्ट्र में राकांपा (शरद पवार) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के साथ मिलकर ही कांग्रेस भाजपा को ज्यादा क्षति पहुंचा पाई। बिहार में अगर राजद वाला गठबंधन नहीं हो तो कांग्रेस कहीं नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से मिलकर भी सातों सीटें जीतने से कांग्रेस भाजपा को नहीं रोक पाई। जहां कांग्रेस ने भाजपा से सीधा मुकाबला किया उनमें राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों में उसने क्षति पहुंचाई, लेकिन भाजपा वहां कांग्रेस से पीछे नहीं गई। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि ऐसे राज्य रहे, जहां सीधे संघर्ष में कांग्रेस एक सीट नहीं पा सकी और भाजपा की एकतरफा जीत हुई। बंगाल में वाम मोर्चा से गठबंधन के बावजूद कांग्रेस सफल नहीं हुई। उसके नेता अधीर रंजन चौधरी तक हार गए। ओडिशा में लोकसभा एवं विधानसभा दोनों में वह हाशिये की पार्टी बनी रही। जबकि केरल में भाजपा इस बार एक सीट जीती है तो वे पर दूसरे स्थान में रही है। अगले चुनाव में अगर उसने अपना जनधार बीड़ा बढ़ाया तो संभव है वहां भी कुछ सीटों का समीकरण बदले। इसी तरह तमिलनाडु में सीटें न जीतते हुए भी भाजपा ने अपना वोट बढ़ाया है।

आम चुनाव परिणाम के इन तथ्यों को ध्यान में रखें तो यथार्थ में कांग्रेस के लिए वैसी उत्साहजनक तस्वीर नहीं नजर आएगी, जैसी दिखाने की कोशिश हो रही है। लगता है कांग्रेस भाजपा की सीटें घटने को ही अपनी बड़ी सफलता मानकर आनंदित हो रही है और इस उत्साह में अपना सही मूल्यांकन नहीं कर पा रही है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन जीने का ढंग

यदि कोई व्यक्ति कलात्मक ढंग से जीता है तो उसका जीवन बहुत सार्थक और सफल बन जाता है। यदि वह जीवन जीने की कला को नहीं जानता तो उसका जीवन नीरस, बोझिल और निरर्थक हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है जीवन में सकारात्मक सोच रखना। जीवन के प्रति हर क्षण जागरूक होना। याद रखें कि दुनिया में सिर्फ दो ही व्यक्ति संपूर्ण हैं। एक मर चुका है, दूसरा अभी पैदा नहीं हुआ है। प्रसिद्धि एवं धन उस समुद्री जल के समान हैं, जितना ज्यादा हम पीते हैं, उतना ही प्यासे होते जाते हैं। जीवन में जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं, उतने ही दुख भी बढ़ जाते हैं।

हम सब जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कुछ ऐसा, जिससे अलग पहचान बन सके। यह चाहते सब हैं, पर कामयाब बहुत कम ही हो पाते हैं। कारण कि हम खुद को पूरी तरह अपने काम में डुबो नहीं पाते। हम यह नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए जरूरी है कि हम ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। इसके लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान होना बेहद जरूरी है। जीवन में अच्छा या बुरा, सब कुछ घटित होता रहता है। मूल बात है कि आप क्या सोच रहे हैं? अपने सोच के अलावा किसी और चीज पर हमारा काबू भी नहीं होता। हमारे ज्यादातर दुख हमारी अपनी उम्मीदों से पैदा होते हैं। इनमें से भी कई जमीन से न जुड़कर खयाली होती हैं। इसी कारण एक बार असफल होने पर हम दोबारा कोशिश नहीं करते। वर्तमान जीवनशैली के चलते हमारे जीवन में भागदौड़, अनचाही प्रतिस्पर्धा, हड़बड़ी आदि कई ऐसे नकारात्मक तत्व समा गए हैं, जो जीवन को कठिन बना रहे हैं। शरीर स्वस्थ रहे, यह जीवन का पहला लक्ष्य है। दूसरा है मन स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। तीसरा है भावनाएं स्वस्थ रहें, निर्मल रहें। निश्चिंताभ्रम विचार न आएं, मैत्री और करुणा का विकास होता रहे। ये सब जीवनरूपी उद्यान की हरा-भरा बनाने के लिए जरूरी हैं।

ललित गर्ग

भारत का पहला 'साहित्य शहर'

चेंद्रराज सुथार

साहित्य समाज के लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करता है, जो इसके मूल्यों, संघर्षों और आकांक्षाओं को दर्शाता है

हाल में उत्तरी केरल में स्थित कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत का पहला 'साहित्य शहर' (सिटी आफ लिटरेचर) घोषित किया गया है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में कालीकट के नाम से मशहूर कोझिकोड को साहित्य के शहर के रूप में मान्यता मिलना न केवल इसकी ऐतिहासिक विरासत का, बल्कि इसके मजबूत साहित्यिक बुनियादी ढांचे और पहलों का भी प्रमाण है। शहर में 500 से अधिक पुस्तकालय और 70 प्रकाशन गृह हैं, जो सालाना 400 से 500 किताबें प्रकाशित करते हैं। ये संस्थान शहर के निवासियों के बीच साहित्य और ज्ञान के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुस्तकालयों और प्रकाशन गृहों के इतने विशाल नेटवर्क की मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है कि साहित्यिक संसाधन व्यापक पाठकों तक पहुंचें, जिससे पढ़ने और लिखने की संस्कृति को बढ़ावा मिले।

कोझिकोड के साहित्यिक परिदृश्य की जीवंतता इसके सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों द्वारा भी उजागर होती है। शहर में कई पुस्तक मेले, साहित्यिक उत्सव और लेखक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जो साहित्य के प्रति उत्साही लोगों के लिए लेखकों और उनके कार्यों से जुड़ने के लिए मंच प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम बौद्धिक आदान-प्रदान और रचनात्मकता प्रोत्साहित कर पाठकों और लेखकों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं। ऐसे कार्यक्रम न केवल साहित्य के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि शहर के सांस्कृतिक पर्यटन में भी योगदान देते हैं। ये कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं कि साहित्य सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए सुलभ हो, समावेशिता और सांस्कृतिक भागीदारी को बढ़ावा दे। साहित्यिक गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी मौखिक परंपराओं और लोककथाओं को संरक्षित करने में भी मदद करती है।

साहित्य समाज के लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करता है, जो इसके मूल्यों, संघर्षों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। साहित्य जीवन को समृद्ध बनाता है, दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और सहानुभूति पैदा करता है। साहित्य एक अधिक समावेशी और समझदार समाज का मार्ग प्रशस्त करता है। किसी भी समाज की सांस्कृतिक और बौद्धिक समृद्धि के लिए साहित्य के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। कोझिकोड का साहित्य के प्रति अपार प्रेम देश और दुनिया के लिए एक मिसाल है। हर शहर और गांव को साहित्य के प्रति ऐसा ही जुनून पैदा करना चाहिए, ताकि पढ़ने की संस्कृति विकसित हो सके। इसके लिए पुस्तकालयों की स्थापना, पुस्तक मेले का आयोजन और स्थानीय लेखकों को समर्थन देना महत्वपूर्ण है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

आपातकाल पर अपना सोच बदले कांग्रेस

'आपातकाल और कांग्रेस' शीर्षक से युक्त संपादकीय में आपातकाल की 50वीं बरसी पर देश की संसद में लाए गए निंदा प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसदों के विरोध को लेकर नेता विपक्षी दल राहुल गांधी को जो नसीहत दी गई है, वह कांग्रेस के लिए गौरतलब है। वस्तुतः आपातकाल के संदर्भ में कांग्रेस को अब अपना सोच बदल लेना चाहिए। राहुल गांधी अपनी दादी द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल को भुला देने की बात करते हैं, जबकि देश के भावी नेताओं को इसे हमेशा याद रखने की जरूरत है ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। लोकसभा में नेता विपक्षी दल का महत्वपूर्ण दायित्व संभालने वाले राहुल गांधी को भी अब आपातकाल को लेकर अपने सोच स्पष्ट कर देने चाहिए ताकि लोकसभा मंडप की अग्रिम पंक्ति में राहुल के साथ बैठने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव को असमंजस की स्थिति का सामना न करना पड़े। इस संदर्भ में यह स्मरणीय है कि 1975 के आपातकाल में समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव को भी जेल में बंद कर दिया गया था। इन्हीं मुलायम सिंह यादव ने उप्र में सपा की सरकार बनने पर आपातकाल के दौरान जेल में निरुद्ध किए गए लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन देकर सम्मानित किया था। ऐसे में उनके पुत्र अखिलेश यादव आज भले ही कांग्रेस के बगलगीर हों, लेकिन वह आपातकाल को कभी सही नहीं ठहरा सकते। संसद में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी को इसे समझने की जरूरत है। कांग्रेस पिछले 50 वर्षों से भले ही संविधान को कुचलने वाले आपातकाल को सही ठहराने की हिमाकत करती रही हो, लेकिन अब उसे सुधर जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से 1975 के आपातकाल को संविधान विरोधी बताकर इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूल के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक राहुल गांधी का संविधान बचाने वाला शिगूफा अर्थहीन ही रहेगा।

pandeyvp1960@gmail.com

जनता को भ्रष्टाचार नहीं पसंद

आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार और राजनीतिक शुचिता की बात की थी। पार्टी द्वारा देश के बड़े-बड़े एवं वरिष्ठतम नेताओं पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए गए, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कितना हास्यास्पद है कि केजरीवाल द्वारा आरोपित लगभग सभी नेता बाहर हैं और वह स्वयं शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। देश में सबसे विचित्र राजनीतिक स्थिति तब उत्पन्न हुई जब आम आदमी पार्टी ने आइएनडीआइए में शामिल होकर स्वयं द्वारा निर्धारित आरोपितों से हाथ मिला लिया। क्या ऐसी ओछी राजनीति सुविधा और सत्तालोलुपता की राजनीति नहीं कहलाएगी? कितना दुखद है कि देश की राजधानी दिल्ली में वह भी मुख्यमंत्री आवास में आम आदमी पार्टी की वर्तमान राज्यसभा सांसद और पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा मुख्यमंत्री के पीएस पर पिटाई के आरोप लगाए गए। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता द्वारा कांग्रेस एवं आप के गठबंधन को एक भी सीट न देना निश्चित ही लोगों के आक्रोश को दर्शाता है।

दीपक गौतम, सेनीपत

युवाओं के हाथ में भारतीय राजनीति

इस चुनाव में भारतीय राजनीति में नए पंक्ति के नेता उभरे, जिनमें अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। ये आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये अपने व्यक्तित्व और प्रभावशाली नेतृत्व के बल पर देश के अंदर प्रभावशाली लीडर के रूप में उभरकर सामने आए हैं। जिस तरह इन्होंने अपने-अपने दलों की बागडोर संभाली और पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाया, इसमें इनकी राजनीतिक परिपक्वता साफ तौर पर झलकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक युवाओं का देश है। ऐसे में भारतीय राजनीति में इस तरह के युवा प्रभावशाली नेताओं का आन भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

हिन्दुस्तान 1936

अभिभाषण का भाव

अठारहवीं लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का अभिभाषण न केवल विश्वास जगाने की अच्छी कोशिश है, बल्कि सत्ता पक्ष की राजनीति का भी स्पष्ट संकेत है। राष्ट्रपति ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया। परीक्षाओं के साथ निरंतर हो रहे खिलवाड़ की वजह से किशोरों और युवा पीढ़ी में चिंता व्याप्त है। शिकायतों के प्रति सरकार को गंभीर होना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कथित गड़बड़ी का उल्लेख किया और वादा किया कि उनकी सरकार निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित करेगी। वास्तव में, युवा पीढ़ी और देश यही चाहता है कि परीक्षाओं को चाक-चौबंद बनाया जाए। उनसे खिलवाड़ करने वाले रसूखदारों के दुस्साहस को मुंहतोड़ जवाब मिलना ही चाहिए। राष्ट्रपति ने सही कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर विचार करने की जरूरत है।

राष्ट्रपति ने संसद के सभी सदस्यों को सलाह दी है कि सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए संसदीय कार्यवाही को बाधित नहीं किया जाए। यह बात छिपी हुई नहीं है कि संसद का समय बड़े पैमाने पर हंगामे की भेंट चढ़ता है। राष्ट्रपति की इस सदिच्छा का सम्मान सांसदों का कर्तव्य होना चाहिए। विरोध अपनी जगह है, जहां सांसद सहमत नहीं होंगे, वहां उन्हें नाराजगी जताने में हिचकना नहीं चाहिए, पर सदन में अनावश्यक शोर करना, मात्र विरोध के लिए विरोध करना बंद हो जाना चाहिए। देश की सर्वोच्च पंचायत फिजूल की टीका-टिप्पणियों के लिए कतई नहीं है। 18वीं लोकसभा में अगर कम से कम हंगामा और ज्यादा से ज्यादा काम हो, तो देश की तरक्की को बल मिलेगा। हंगामा या समय की बर्बादी सत्ता पक्ष की वजह से हो या विपक्ष की वजह से, नुकसान देश को होता है। राष्ट्रपति ने सांसदों को याद दिलाया है कि सदन के सभी सदस्यों के लिए लोकहित सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह भी संकेत दिया है कि सरकार आगामी बजट के दौरान कई बड़ी घोषणाएं करेगी। पहले से ही यह उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी बजट देश की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को प्रभावित करने वाला हो सकता है। इससे देश में आर्थिक सुधार की गति बढ़ेगी। यहां लोग यही उम्मीद करेंगे कि आर्थिक सुधार आम लोगों के अनुरूप हों, कंपनियों की सुनवाई हो, पर लोगों की जरूरतों को देखते हुए सुधार के कदम उठाए जाएं। ऐसे कदम जरूरी हैं, जिनसे रोजगार में वृद्धि हो।

परीक्षाओं के साथ खिलवाड़ को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने सही कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार की जरूरत है।

राष्ट्रपति का यह कहना भी प्रशंसनीय है कि निवेश के लिए हमारे राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा होनी चाहिए। निवेश आमंत्रित करने के लिए, बेहतर नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिस्पर्द्धा का भाव आना जरूरी है। राज्य जब एक-दूसरे से सीखेंगे और एक-दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, तब देश की तरक्की तेज होगी। कुल मिलाकर, अभिभाषण स्वागतयोग्य है, पर हमेशा की तरह इस बार भी अभिभाषण की बातें विपक्ष को पसंद नहीं आई हैं। यहां यह समझना चाहिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को केंद्र सरकार तैयार करती है और जब इसमें आपातकाल को काला अध्याय के रूप में याद किया गया, तो विपक्ष की नाराजगी उभर आई। आपातकाल को हम भुला नहीं सकते, पर उसे बार-बार याद करके कटु यादों को ताजा करने से ज्यादा बेहतर है कि हम सबक लें और लोकतंत्र की ज्यादा मजबूती के लिए काम करें।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 28 जून, 1949

सहायक खाद्य

खाद्यान्नों की हमारे देश में कमी है और विदेशों से अन्न मंगाकर हम जो उसकी पूर्ति कर रहे हैं, उससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ रहा है, इस बारे में दो मत नहीं हो सकते। इसका हल दो ही तरह से संभव है। या तो हम अपनी उपज बढ़ायें और फिर भी कमी रहे, तो सहायक खाद्य-पदार्थों की उत्पत्ति-वृद्धि एवं उन्हें काम में लाने की कोशिश करें, या अन्न के आयात को अपने औद्योगिक अथवा कच्चे माल के निर्यात की वृद्धि द्वारा सन्तुलित करें। दोनों में से एक अथवा कम-बढ़ दोनों ही बातें करना आवश्यक है। अतः इनमें से जो भी बात की जाये, उसे सबका सहयोग मिलना चाहिए।सबसे पहला प्रयत्न इस दिशा में उपज-वृद्धि का ही होना चाहिए। 'अधिक खाद्यान्न पैदा करो' की सरकारी हलचल हम बरसों से देख भी रहे हैं, फिर भी यदि इस दिशा में कोई सन्तोषप्रद परिणाम सामने नहीं आया तो समझना चाहिए कि या तो इससे सम्बन्धी सरकारी हलचल सदोष रही है या फिर हमारे यहां उपज-वृद्धि की कोई गुंजाइश ही नहीं है। खासकर जब डा. राजेन्द्र प्रसाद जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, जो कि खुद भी सरकार के खाद्य विभाग का संचालन कर चुके हैं, हमें बताते हैं कि हमारे यहां खाद्य की कमी केवल १० प्रतिशत है और यदि सौ मन उपज को हम सावधानी से खेती करके एक सौ दस मन कर सके, यानी हर दस मन उपज में केवल एक मन उपज ही बढ़ा सके तो भी यह पूरी हो सकती है। तो हमारी समझ में नहीं आता कि अन्नाभाव का इतना शोर क्यों है और अभी तक वह कमी पूरी क्यों नहीं हो पाई। यह भी आज कोई नहीं मानता कि हमारे यहां अन्नोत्पादन-वृद्धि की गुंजाइश नहीं है। फिर, ऐसा नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया इसका पता लगाना चाहिए और जो कारण इसमें बाधक रहे हों, उन्हें दूर कर यह काम करना चाहिए।

मालूम यह पड़ता है कि सम्बन्धी सरकारी विभाग इस दिशा में झंझट पाकर विदेशों से अन्न मंगाने के मार्ग को आसान पा रहा है, फिर उससे चाहे देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़े। आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर की बात हम इसलिए कहते हैं, क्योंकि हमारे विदेशी व्यापार की असंतुलितता का कारण विदेशों से अन्न के भारी आयात को ही बताया जा रहा है।

शेयर बाजार की समृद्धि कैसे हो साझा

यहां स्कैन करें

अरुण कुमार | वरिष्ठ अर्थशास्त्री

शेयर बाजार से वास्तविक लाभ हासिल करने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धनाढ्यों की नजर से देखने के बजाय मध्यवर्ग या गरीबों के नजरिये से देखना चाहिए।

शेयर बाजार के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने से निवेशक खुश हैं। गुरुवार को भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 79,000 के ऊपर चला गया था, जो इसके इतिहास में पहली बार हुआ है। निफ्टी भी कमोबेश इसी गति से आगे बढ़ रहा है और वह 24,000 के करीब पहुंचता दिखा। ये आंकड़े निवेशकों के लिए भले मुफीद हों, लेकिन आम भारतीय इसे कौतुक की नजर से ही देखते हैं। ऐसा क्यों?

दरअसल, शेयर बाजार में करीब 6,000 सूचीबद्ध कंपनियां हैं, जिनमें मूलतः तीन तरह के निवेशक निवेश करते हैं। पहला वे बड़े निवेशक हैं, जो अमूमन कंपनियों के मालिक होते हैं। आबादी के लिहाज से ये देश के 0.1 प्रतिशत लोग हैं और शेयर बाजार को कमोबेश यही नियंत्रित करते हैं। हालांकि, मध्य वर्ग के निवेशक भी लाख-दो लाख रुपये का निवेश करते हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी इन 0.1 प्रतिशत लोगों को ही माना जाता है। दूसरे वे निवेशक होते हैं, जो बड़े करदाता हैं और जिनकी हिस्सेदारी कुल जनसंख्या में 1.1 प्रतिशत है। जबकि, तीसरे निवेशक करीब आठ करोड़ वे लोग हैं, जो बहुत मामूली रकम निवेश करते हैं। चूंकि शेयर बाजार के गुणा-भाग खासतौर से इनसाइडर ट्रेडिंग (कंपनियों की आंतरिक सूचनाओं को हासिल करना) या मैन्युपुलेशन (तिकड़मबाजी) से ये अनजान रहते हैं, इसलिए बाजार के गिरने का नुकसान इनको ही अधिक होता है, जबकि ज्यादातर फायदा शुरुआती दो तरह के निवेशकों के हिस्से में जाता है।

शेयर बाजार को लेकर यह भी समझने की जरूरत है कि यह भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित होता है। अगर आज बाजार ऊपर है, तो निवेशकों को यही उम्मीद होती है कि आने वाले दिनों में यह अच्छा करने वाला है। यही कारण है कि जब उन्हें किसी संकट का एहसास होता है, तो निवेशक अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और शेयर बाजार गिरने लगता है। इसीलिए, इससे जुड़ी उम्मीदों व अपेक्षाओं को बरकरार रखने के लिए तमाम सरकारी वित्तीय संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है।

शेयर बाजार में संगठित क्षेत्र की कंपनियां ही होती हैं। यही वजह है कि अपने देश में करीब छह लाख लघु व मध्यम कंपनियों और छह करोड़ सूक्ष्म कंपनियों का शेयर बाजार प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी इसमें इन कंपनियों के शेयर नहीं होते। जबकि, ज्यादातर रोजगार यही कंपनियां देती हैं। यह मान लिया जाता है कि बड़ी कंपनियां यदि अच्छा करेंगी, तो उसका फायदा छोटी-छोटी कंपनियों को भी होगा। मगर दिक्कत यह है कि बड़ी कंपनियां भी अब तमाम तरह के उत्पाद बनाने लगी हैं और हम भी ऑनलाइन सामान खरीदना पसंद करने लगे हैं, इसलिए छोटी कंपनियों की मांग बड़ी कंपनियों के खाते में जाने लगी है, जिससे प्रतिस्पर्द्धा में छोटी कंपनियां पिछड़ने लगी हैं। इसका असर देश के रोजगार परिदृश्य पर भी दिख रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू कृषि भी है और दुर्भाग्य से इसका भी शेयर बाजार प्रतिनिधित्व नहीं करता। हां, कृषि में यदि कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो उसका परोक्ष लाभ जरूर शेयर बाजार को मिलता है, लेकिन कृषि की बेहतरी के बारे में शेयर बाजार शायद ही सोचता है। कृषि में हिस्सेदारी निभाने वाले 85 फीसदी छोटे किसानों की आर्थिकी तो इससे पूरी तरह दूर है। इन्हीं सब वजहों से माना जाता है कि महज छह फीसदी आबादी की इसमें हिस्सेदारी है, जो संगठित क्षेत्र के हैं, जबकि एक बड़ी संख्या (94 फीसदी) असंगठित क्षेत्र में होने के कारण शेयर बाजार से दूर है।

जाहिर है, शेयर बाजार में नीतिगत बदलाव की जरूरत है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इसका ज्यादातर फायदा आमतौर पर 0.1 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत आबादी (शुरुआती दो तरह के निवेशकों) के खाते में चला जाता है, जिससे आर्थिक असमानता में इजाफा हो रहा है। सरकार को शेयर बाजार के लाभांश (कैपिटल गेन्स) पर कर के रूप में पैसे जरूर मिलते हैं, लेकिन चूंकि अपने देश में संपत्ति कर (वेल्थ टैक्स, यानी धनाढ्यों पर लगने वाला अतिरिक्त कर) खत्म कर दिया गया है, इसलिए शेयर बाजार में उछाल से सरकारी खजाने में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती। अच्छा होगा कि सरकार फिर से इस टैक्स को शुरू करे, जिससे उसके राजस्व में वृद्धि होगी। कुछ इसी तरह का टैक्स संपत्ति के पीढ़ीगत हस्तांतरण पर भी लगाया जाना चाहिए, जिसे 'इनेहरिटेंस टैक्स', यानी उत्तराधिकार कर कहा जाता है। हमारे यहां ये दोनों कर नहीं हैं, जबकि गैर-बराबरी कम करने में इनकी काफी कारगर माना जाता है।

असल में, शेयर बाजार से वास्तविक लाभ हासिल करने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धनाढ्यों की नजर से देखने के बजाय मध्यवर्ग या गरीबों के नजरिये से देखना चाहिए। उनकी तरक्की से अर्थव्यवस्था को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अमीर आदमी अपनी आमदनी का मामूली हिस्सा खर्च करता है, जबकि गरीब तुलनात्मक रूप से अधिक खर्च करता है। इससे बाजार में मांग पैदा होती है और निवेश बढ़ने की उम्मीद बंधती है। इसका किस तरह कंपनियों को भी फायदा होता है, इसका संकेत 1911 में फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मांग जब तक नहीं होगी, तब तक व्यापक उत्पादन का कोई अर्थ नहीं, जबकि 'मास प्रोडक्शन' अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी वारेन बफेट ने 2007-09 की मंदी के बाद कहा था कि पूंजीवाद को बचाने के लिए पूंजीपतियों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, जिसका समर्थन जॉर्ज सोरोस जैसे अरब-खरबपतियों ने भी किया था।

भारत में अभी इसके लिए उचित समय भी है। अभी शेयर बाजार में सब कुछ ठीक चल रहा है, जिसका अर्थ है कि संगठित क्षेत्र अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसकी मांग बढ़ चली है। यह असंगठित क्षेत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है और चूंकि हम इसे शेयर बाजार का हिस्सा नहीं बना सकते, इसलिए संगठित क्षेत्र से टैक्स वसूलकर उसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। संपत्ति या उत्तराधिकार कर का उपयोग ग्रामीण विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मदों की बेहतरी में किया जा सकता है, जिनमें आज भी पर्याप्त खर्च नहीं किया जा रहा। इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा। वैसे भी, अगर असंगठित क्षेत्र में मांग बढ़ेगी, तो उसका परोक्ष फायदा संगठित क्षेत्र को भी होगा, क्योंकि लोग उन उत्पादों को भी खरीदेंगे, जिनको बड़ी-बड़ी कंपनियां बनाती हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

साइबर संसार को कई संदेश दे गई असांजे की रिहाई

यहां स्कैन करें

पवन दुग्गल | साइबर कानून विशेषज्ञ

साइबर विशेषज्ञ, हैकर, संपादक जूलियन असांजे की रिहाई कोई सामान्य घटना नहीं है। यह रिहाई बदलते दौर का एक संकेत है। यह नई साइबर व्यवस्था का युग है, जिसमें तीन बातें साफ तौर पर हमारे सामने हैं। एक, सरकारें बहुत मजबूत होती जा रही हैं। दूसरी, साइबर सुरक्षा में सेंधमारी रोजमर्रा की समस्या बन गई है। तीसरी बात, साइबर अपराध हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। इन तीनों बातों से जोड़ते हुए ही जूलियन असांजे के मामले को देखना चाहिए।

जूलियन के खिलाफ मुकदमा इसलिए चलाया गया था, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी सरकार, अमेरिकी हितों और अमेरिकी सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं हासिल कीं और विकीलीक्स पर प्रसारित कर दिया था। अमेरिका का कहना है कि विकीलीक्स में प्रकाशन से उसे बहुत नुकसान पहुंचा है। खुलासों के बाद अमेरिका उनके पीछे पड़ गया और वह गिरफ्तारी से बचते हुए भागते रहे। अनेक देशों में छिपते फिरते रहे और अंततः ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिए गए।

हमें यह समझना होगा कि जूलियन ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तब जो प्रधानमंत्री बने, उनके लिए जूलियन की रिहाई प्राथमिकता बन गई। कूटनीतिक स्तर पर रिहाई के लिए बहुत प्रयास हुए। अंततः एक समझौता या सौदा हुआ। सौदा हुआ, पर अमेरिका ने कहा कि मैं अपने आरोप खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि लगाए गए आरोप बेहद गंभीर किस्म के हैं, फिर भी यदि जूलियन असांजे माफी मांगते हैं और अपने आपको दोषी स्वीकार करते हैं, तो हम उनके द्वारा अब तक काटी गई सजा को पर्याप्त मानकर उन्हें रिहा कर देंगे। इसके बाद ही उनकी रिहाई के लिए रास्ता निकला। वह एक अमेरिकी अदालत में पेश हुए और खुद को दोषी स्वीकार किया, तब उन्हें छोड़ा गया। अब वह स्वदेश ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं।

जूलियन असांजे बहुत भाग्यशाली रहे कि उनकी रिहाई के लिए राजनीतिक संधि हुई है, पर हर इंसान इतना खुशकिस्मत नहीं है।

कुल मिलाकर, यह रिहाई एक अप्रत्याशित घटना है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनकी रिहाई हो जाएगी। वास्तव में, यह दुनिया में मजबूत होती सरकारों के प्रयासों का नतीजा है। यहां ऑस्ट्रेलिया सरकार अगर मजबूती से रिहाई के प्रयास नहीं करती, तो वाकई अमेरिका जूलियन को इतनी जल्दी नहीं छोड़ता।

इस मामले को व्यापकता में देखना चाहिए। आज दुनिया में अलग-अलग सरकारों के पास अपने-अपने साइबर कानून हैं। साइबर अपराध को बहुत गंभीरता से लेने की शुरुआत हो चुकी है। पहला संदेश यही जाता है कि अगर आप किसी का डाटा उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप किसी सरकार का गोपनीय डाटा उजागर कर देते हैं, तो वह सरकार या राष्ट्र चुप नहीं बैठेगा, आप पर मुकदमे करेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आपको गिरफ्त में ले लिया जाएगा।

दूसरा संदेश यह है कि कोई भी किसी सरकार के बारे में किसी गोपनीय जानकारी का पता न लगाए, तो साइबर कानूनों से बच सकता है। अगर दुनिया की कोई भी सरकार आप पर सुरक्षा संबंधी डाटा लीक करने का इल्जाम लगाती है, तो फिर दूसरी सरकारें आपका बचाव नहीं करेंगी।

जूलियन असांजे बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि उनकी रिहाई के लिए राजनीतिक-कूटनीतिक संधि हुई है, पर हर इंसान उनकी तरह खुशकिस्मत नहीं रहेगा। यह भी ध्यान रहे कि वह तभी छूट सके हैं, जब उन्होंने खुद को दोषी मान लिया है, अमेरिका भी इस बात से खुश है कि उसके लगाए गए आरोप साबित हुए हैं।

इस रिहाई के बाद बहुत सारी सरकारें सजग हो जाएंगी और अपने डाटा लीक के मामलों को गंभीरता से लेंगी। यह बात भी सामने आ गई है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सरकार से संबंधित गोपनीय सूचनाएं प्रकाशित नहीं कर सकते। पत्रकारिता का अर्थ यह नहीं कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने लगें। अब अनेक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा, क्योंकि सरकारें पहले की तुलना में ज्यादा सजग हो जाएंगी। इसका एक असर यह भी होगा कि विकीलीक्स जैसे प्रयोग कम होंगे या नहीं हो पाएंगे। अब ज्यादा से ज्यादा डाटा डार्क नेट पर स्थानांतरित होते जाएंगे। डार्क नेट पर साइबर अपराधियों का पता लगाना अब भी मुश्किल है। डाटा चोरी के लिए एआई का इस्तेमाल भी बढ़ने वाला है, तो कुल मिलाकर, साइबर चुनौतियां बढ़ने वाली हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मृत्यु से डरते थॉमस

मैं एक ऐसे शख्स (काल्पनिक नाम- थॉमस) को जानता हूं, जिन्होंने एक हजार डॉक्टरों से इलाज कराए हैं। उनकी उम्र 80 साल है। फिर भी, एक हजार बहुत बड़ी संख्या होती है। एक साल में उन्होंने औसतन 12 नए डॉक्टरों को दिखाया। कभी-कभी तो थॉमस एक दिन में तीन-तीन डॉक्टरों से सलाह लेते हैं।

थॉमस के कुछ दोस्त डॉक्टर हैं, तो कुछ डॉक्टर उनके दोस्त बन जाते हैं। उनके इन एक हजार डॉक्टरों में जूनियर से लेकर सीनियर, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर से लेकर निजी प्रैक्टिस करने वाले, सामान्य चिकित्सक से लेकर विशेषज्ञ तक शामिल हैं। पुरुष, महिलाएं, विदेशी, स्थानीय सभी तरह के डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया है। कभी महज रक्तचाप मापने के लिए, तो कभी सीने में अचानक उठे दर्द जैसे गंभीर मामले के लिए। अपने जीवनकाल में डॉक्टरों की फीस-जांच आदि पर वह लगभग 2,30,000 डॉलर खर्च कर चुके हैं। थॉमस को इसका कोई पछतावा नहीं है। लोग अपने शौक पूरे करने पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन थॉमस के लिए यह डॉक्टर, डॉक्टर और डॉक्टर हैं। दुखद यह है कि थॉमस को हाल ही में फेफड़ों के कैंसर का पता चला और उन्हें मेरे पास भेजा गया था।

थॉमस मुझे एक सुलझे हुए सज्जन व्यक्ति लगे। उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, अपना मेडिकल इतिहास स्पष्ट रूप से बताया और मेरे अधिकांश प्रश्नों का उचित तरीके से उत्तर भी दिया। थॉमस मरने से डरते हैं। हममें से बहुत से लोग कैंसर पीड़ित हों या नहीं, पर मृत्यु के भय को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

अपनी मृत्यु के डर के अलावा थॉमस ने डॉक्टरों के प्रति अविश्वास का भी खुलासा किया। इलाज पर निर्णय लेने से पहले वह अधिक से अधिक राय ले रहे थे। उनके अपने संदेह थे। कुछ लोग थॉमस को 'थानाटोफोबिया' का शिकार कह सकते हैं। थानाटोफोबिया में व्यक्ति को अपनी या किसी प्रिय की मृत्यु का भय इस कदर सताता रहता है कि वह मनोवैज्ञानिक रूप से अपंग हो जाता है। मगर यह बहुत सुविधाजनक लेबल लगाना होगा, क्योंकि थॉमस सफल उद्यमी हैं व सामाजिक रूप से कुशल भी।

मैं थॉमस को कैंसर से लड़ने में मदद करूंगा। उनको जज नहीं करूंगा। मैं मौत के उनके डर का 'मेडिकलीकरण' नहीं करूंगा। यही ईसानियत है और इसकी कोई दवा नहीं होती।

हम हर छोटे से छोटे लक्षण या तकलीफ का इलाज करते हैं- शिशु के अत्यधिक रोने से लेकर किशोर के गुस्से, वेतनभोगी व्यक्ति की उदासी तक। थॉमस के पास कई डॉक्टरों को दिखाने का समय व पैसा है और ऐसा करना उन्हें अच्छा लगता है। यह उसके लिए उपचारात्मक है। मैं थॉमस को कैंसर से लड़ने में मदद करूंगा। उन्हें अनावश्यक रक्त परीक्षण और सिटी स्कैन कराने से रोकूंगा। मैं उन्हें जज नहीं करूंगा और सबसे बढ़कर, मैं मौत के उनके डर का 'मेडिकलीकरण' नहीं करूंगा। यही ईसानियत है और इसकी कोई दवा नहीं होती।

पाउलो कोएल्हो

जो बाइडन | अमेरिकी राष्ट्रपति

हमें मतपत्रों के जरिये अपने लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। लोकतंत्र पर डोनाल्ड ट्रंप का हमला सिर्फ उनके अतीत का हिस्सा नहीं है... बल्कि यह भविष्य के लिए उनके वादे की तरह भी है।

जय फलस्तीन बोलने में कैसा ऐतराज

पिछली सदी के तीसरे दशक की बात है। तब तक फलस्तीनी इलाके में यहूदी राज्य की नींव पड़ चुकी थी। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था और ब्रिटेन व फ्रांस ने मिलकर मध्य-पूर्व का बंटवारा कर लिया था। लीग ऑफ नेशंस (संयुक्त राष्ट्र से पहले की अंतरराष्ट्रीय संस्था) की निगरानी में सीरिया पर फ्रांस, तो इराक व फलस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था। चूंकि ब्रिटेन की नीति यहूदियों को बसाने की थी, इसलिए पहले महायुद्ध के बाद लाखों यहूदी फलस्तीन में बसने के लिए आए। यहूदियों के इसी पलायन के खिलाफ सन् 1936 में अरब विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जब फलस्तीन में यह सब हो रहा था, तब हिन्दुस्तान में भी अंग्रेजों का शासन था, लेकिन यहां ब्रिटिश हुकूमत के दमन के बावजूद पराधीन शासन का विरोध करने वाले देशभक्तों की कमी नहीं थी। इसी सूरते-हाल में इलाहाबाद में फलस्तीन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें रफ़ी मनोहर लोहिया, जेबी कृपलानी, मौलाना शौकत अली जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के भाग लेने की बात कही जाती है। साल 1936 के शुरुआती महीनों में कांग्रेस ने फलस्तीन का खुलकर समर्थन किया और 27 सितंबर, 1936 को भारत में पहला फलस्तीन दिवस मनाया गया। सोचिए जरा, 1936 का पराधीन भारत भी फलस्तीनियों के साथ खड़ा था, पर आज यदि संसद में फलस्तीन की जय बोली जाती है, तो सदस्यता छीनने की मांग आ जाती है।

देखा जाए, तो असदुद्दीन ओवैसी ने संसद सदस्य की शपथ लेने के बाद 'जय फलस्तीन' का नारा लगाकर पूरी दुनिया को एक खास पैगाम दिया है कि हम और हमारा देश भारत हमेशा की तरह आज भी फलस्तीन और वहां की जनता के साथ मजबूती से खड़ा है। यह एक संदेश है कि इजरायल की नीतियों व उसकी नाइंसाफी का भारत पुरजोर विरोध करता है। अच्छा तो यह होता कि फलस्तीन का नाम लेने के कारण ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा किया जाता। उनकी बातों को और मजबूती से दोहराया जाता, ताकि पूरी दुनिया को पता चलता कि भारत कितना इंसाफ पसंद है। मगर इन सबके बजाय ओवैसी साहब को लानत मलामत भेजी जा रही है। क्या विडंबना है कि 2024 के भारत में 'जय फलस्तीन' बोलने पर विवाद हो रहा है, जबकि फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने वाले पहले देशों में भारत भी रहा है। ओवैसी की आलोचना करने वाले बेशक उनकी नीतियों की आलोचना करें, लेकिन फलस्तीन पर उन्हें जिस तरह घेरा जा रहा है, वह उचित नहीं।

अतहर इमाम, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

फलस्तीन

संसद में लगाया गया एक अनुचित नारा

लोकसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण में माननीय सांसदों द्वारा अपने मन के उद्गार और नायकों के सम्मान में लगाए गए नारे 'अनेकता में एकता' को प्रतिबिंबित कर रहे थे। जय श्रीराम, जय भीम, जय संविधान, भारत माता की जय के नारों से स्पष्ट लग रहा था कि सांसद अपनी पार्टी लाइन को ध्यान में रखते हुए जयघोष कर रहे हैं। सांसदों द्वारा इन नारों के जरिये अपनी भावना को व्यक्त करना किसी हद तक उचित जान पड़ रहा था, पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी का 'जय फलस्तीन' व सांसद छत्रपाल गंगवार का 'जय हिंदू राष्ट्र' का उद्घोष अनुचित माना जाएगा। इनकी स्वाभाविक ही निंदा हो रही। किसी विवादित विषय का यूं उद्घोष करना गलत है। यह ठीक है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते समय इसकी मर्यादा का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। अमर्यादित आचरण, वह भी सांसदों द्वारा, कतई सही नहीं ठहराए जा सकते। हम सभी अपेक्षा करते हैं कि सदन में राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर राष्ट्र की प्रगति, सुरक्षा के लिए और जनता के सवालों पर सार्थक बहस होगी और विवाद की जगह सार्थक संवाद होगा। माननीयों द्वारा संसद में एक मजबूत राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की सहभागिता दिखाई देगी। मगर शुरुआत प्रतिकूल स्थितियों के साथ हुई है। फिर भी, लोकसभा में इस बार सतरंगी झलक दिखाई दे रही है, जिसमें भारत के 140 करोड़ लोगों की आशा पूरी होने की अपार संभावनाएं हैं।

विरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

भारत के नारे क्यों नहीं लगाए

एआईएमआईएम के मुखिया व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ के पश्चात जो नारा लगाया, वह नहीं लगाना चाहिए था। यह सही है कि अन्य सांसदों ने भी शपथ के बाद अपने-अपने विचार से नारे लगाए, लेकिन ओवैसी का नारा संविधानिक नहीं था। यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत उनको अयोग्य ठहरने की मांग जोर पकड़ने लगी है। विरोध सिर्फ सांसद ही नहीं कर रहे, आम जनता में भी उनके इस कृत्य की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। आखिर क्यों उन्होंने सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए फलस्तीन की जय का नारा लगाया? उन्होंने 'भारत माता की जय' क्यों नहीं कहा? हालांकि, अब इस नारे को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, बावजूद इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के विवादित नारों, बयानों आदि से हमारे जन-प्रतिनिधियों को बचना चाहिए। इससे उनकी गरिमा भी बनी रहेगी और सदन की भी।

महेश नेनावा, टिप्पणीकार